भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1594

गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित अर्थव्यवस्था</u>

1594. डॉ. राजश्री मल्लिक: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हरित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत् विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): आईएमएफ की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), अक्टूबर 2022 के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है।

सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ उपाय अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

'हरित अर्थव्यवस्था' के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1594 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए किए गए मुख्य उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाओं की शुरुआत करना,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के समेकन के लिए पारेषण योजना,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को एक्सचेंज के माध्यम से सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।
- सरकार अक्षम थर्मल यूनिटों को पूरी सक्रियता से बंद कर रही है। 10वीं योजना से लेकर नवम्बर, 2022 तक 18152 मेगावाट क्षमता की कुल 259 यूनिटें बंद की जा चुकी हैं।
- केवल भारतीय रेलवे द्वारा ही वर्ष 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने से उत्सर्जन में प्रति वर्ष 60 मिलियन टन की कमी आएगी। इसी तरह, भारत के व्यापक एलईडी बल्ब अभियान से उत्सर्जन में प्रति वर्ष 40 मिलियन टन की कमी हो रही है।
- वर्ष 2017 के बाद से सभी थर्मल विद्युत क्षमता वृद्धि केवल सुपर क्रिटिकल यूनिटों के जरिए की जा रही है। इससे फॉसिल फ्यूल की खपत में कमी आएगी और इस प्रकार कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जनों में कमी आएगी।
- देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना,
- परिवहन क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम करने के लिए ईंधन दक्षता मानदंड अधिसूचित करना,
- थर्मल विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास पैलेट की को-फायरिंग की जा रही है,
- उर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

*****